एस सी आर।

सरदार इंदर सिंह

व.

राजस्थान का राज्य

(और संबंधित याचिकाएँ)

(एस. आर. दास सी. जे., वेंकटरामा अय्यर, बी. पी. सिन्हा सिन्हा, एस. के. डी. ए. एस. और गजेन्द्रगडकर जे. जे.)

संवैधानिक कानून-प्रत्यायोजित कानून और सशर्त कानून लेशन-भेदभाव-बाहरी प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करने वाला क़ानून इसके संचालन को बढ़ाने के लिए-वैधता-राजस्थान (किरायेदारों का संरक्षण) अध्यादेश, 1949, (राजस्थान अध्यादेश सं 1949 का IX), एस. एस. 3, 4, 7(1) 15 - राज प्रमुख द्वारा अधिसूचना-वैधता-क्या अध्यादेश कला का उल्लंघन करता है। 14 और भारत के संविधान की धारा 19 (1) (च)।

एस द्वारा। 3(1) राजस्थान (किरायेदारों का संरक्षण) अध्यादेश, 1949, जिसे 21 जून, 1949 को राज द्वारा घोषित किया गया था। राजस्थान के प्रमुख, यह प्रदान किया गया थाः यह लागू होगा। एक बार में, और दो साल की अवधि के लिए लागू रहेगा जब तक कि इस अवधि को राज प्रमुख द्वारा अधिसूचना द्वारा आगे बढ़ाया गया है। राजस्थान राजपत्र में उल्लेख"।

इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज प्रमुख ने 14 जून, 1951 को एक एन. सी. टी. जारी किया, जिसमें कहा गया था कि उपरोक्त अध्यादेश "आगे की अवधि के लिए लागू रहेगा। 21 जून, 1951 से प्रभावी दो वर्षों के लिए और 20 जून को, 1953, उन्होंने एक और अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि अध्यादेश "एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। 20 जून, 1953 की अधिसूचना की वैधता, राज प्रमुख ने 15 फरवरी, 1954 को एक और अध्यादेश जारी किया। एस के लिए टाइट्यूटिंग। 3 21 जून, 1949 के मूल अध्यादेश के अनुसार, निम्नलिखित हैः

" यह तुरंत लागू हो जाएगा और बना रहेगा। पाँच साल की अवधि के लिए बल। इसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया गया था, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 21 जून, 1949 का अध्यादेश और राज प्रमुख द्वारा जारी अधिसूचनाएँ अमान्य थीं आधार (1) वह

एस। 3 अध्यादेश की शक्ति अधिकार से बाहर थी जिसे उसने राज प्रमुख को निर्धारित अवधि बढ़ाने के लिए प्रदान किया था इसमें विधायी शक्ति का एक असंवैधानिक प्रतिनिधि मंडल था, (2) कि 20 जून, 1953 की अधिसूचना खराब थी क्योंकि राजस्थान विधानमंडल का गठन 29 मार्च को किया गया था। 1952, और राज प्रमुख को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया कला द्वारा। 385 उस तारीख को भारत का संविधान आया था। (3) यह कि अध्यादेश कला का उल्लंघन करता है। 14 और 19 (1) (च) संविधान का।

आयोजित किया गयाः (1) अध्यादेश की धारा 3 जहाँ तक वह अधिकृत है राज प्रमुख ने अध्यादेश के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए नाराजगी जताई सशर्त विधान की श्रेणी के भीतर और अधिकार के भीतर है।

एक कानून में एक प्रावधान जो एक बाहरी व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है इसे ऐसे समय पर लागू करने का अधिकार, जिसमें स्वयं का विवेकाधिकार, निर्धारित, सशर्त है और प्रत्यायोजित कानून नहीं है एक सशर्त विधान के रूप में कि विधायिका, इसके बाद कानून को स्व-अधिनियमित करना और तथ्यों पर विचार करने पर तय करना एक बाहरी प्राधिकरण पर एक के लिए अपने संचालन का विस्तार करने की शक्ति आगे की अवधि यदि यह संतुष्ट है कि तथ्यों की स्थिति जिसे कहा जाता है आगे कानून बना हुआ है।

रानी वी. बुराह, (1878) 5 एल. ए. 178, पर निर्भर था। दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 (1951) एस. सी. आर. 747 और बॉम्बे राज्य बनाम। नरोत्तमदास जेठाबाई, (1951) एस. सी. आर. 51, संदर्भित किया गया।

जतिंद्र नाथ गुप्ता बनाम। बिहार राज्य, (1949) एफ. सी. आर. 595, जहाँ तक यह तय किया है कि एक के जीवन का विस्तार करने की शक्ति अधिनियमन वैध रूप से किसी बाहरी प्राधिकारी को प्रदान नहीं किया जा सकता है, से असहमत।

(2) राज प्रमुख ने 20 जून को अधिसूचना जारी की, 1953, उसके चरित्र में उस अधिकार के रूप में जिस पर शक्ति निहित थी एस के तहत ferred। 3 अध्यादेश का और विधायी के रूप में नहीं राज्य का अधिकार और तदनुसार अधिसूचना वैध है।

(3) अध्यादेश को अनुच्छेद के तहत गलत नहीं माना जा सकता है। 14 में

से संविधान इस आधार पर कि एस। 15 अध्यादेश जो प्राधिकृत करता है सरकार किसी भी व्यक्ति या वर्ग को छूट देगी अध्यादेश के संचालन से व्यक्ति उन सिद्धांतों को निर्धारित नहीं करते हैं जिन पर छूट दी जा सकती है छोड़ दिया गया निरंकुश के लिए मायने रखता है और अप्रचलित का विवेक सरकार, क्योंकि, अध्यादेश की प्रस्तावना विधानमंडल की नीति को पर्याप्त स्पष्टता के साथ निर्धारित करती है और जैसा कि शासन करता है। 15, सरकार के निर्णय को दिशाहीन नहीं कहा जा सकता है।

हरिशंकर बागला बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, (1955) 1 एस. सी. आर. 380, 388 पर भरोसा किया। जहाँ अध्यादेश की प्रस्तावना में कहा गया है कि किरायेदारों को संरक्षण देने के लिए एक कानून बनाने के लिए और उन्हें राहत देने के लिए विधायिका यह तय करती है कि कानून को किस तारीख से लागू किया जाना चाहिए, यह विशेष रूप से विधायिका को निर्धारित करने का मामला है, और इसमें भेदभाव के आधार पर अदालतों में सवाल करने के लिए खुला नहीं है। जिनके पास उस तारीख से पहले अपनी भूमि पर किरायेदार थे, वे इसके प्रतिबंधों से मुक्त थे।

(4) अध्यादेश के प्रावधान जो भूमि को बाध्य करते हैं मालिकों को अपनी भूमि पर किरायेदारों को रखने के लिए, जिससे उन्हें उसी की खेती करने से रोका जा सके, अपमानजनक नहीं हैं का उद्देश्य कला के लिए। 19 (1) (च) संविधान की, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 607 एस सी आर।

अध्यादेश भूमि पर खेती करने के मालिक के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं था, बल्कि उसे रोकने के लिए था जब उसने भूमि पर एक किरायेदार को बिना पर्याप्त कारण के उससे छुटकारा पाने से रोक दिया था, और एक कानून जिसके लिए आवश्यक है कि एक मालिक जो खुद मिट्टी का जोतने वाला नहीं है, वह वास्तविक जोतने वाले को कार्यकाल की कुछ निश्चितता का आश्वासन दे, अकेले उस आधार पर अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

ब्लॉक वी। हिर्श (1920) 256 यू. एस. 135: 65 एल. एड. 865, पर भरोसा किया।

मौलिक न्यायनिर्णयः याचिका याचिका सं। 50, 145, 149, 150, 188, 243, 261, 266 और 1955 का 362 और 205, 1956 का।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएं मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारत। पेटी के लिए एम. एम. तिवारी और के. आर. चौधरी याचिका सं. में वक्ता।

50, 150, 243, 261, 266 और 362 1955 से।

याचिका संख्या में याचिकाकर्ताओं के लिए गणपत राय। 145, 149, 188, 1955 का और 1956 का 205। पोरस ए. मेहता और टी. एम. सेन, राज्य के लिए सभी याचिकाओं में राजस्थान और राजस्व बोर्ड।

उदय भान चौधरी, उत्तरदाताओं के लिए संख्या। 2 और 3 1955 की याचिका संख्या 145 में।

उत्तरदाताओं के लिए के. पी. गुप्ता संख्या। 4 याचिका में 6 तक 1955 का सं. 149।

ताराचंद बृजमोहन लाल, उत्तरदाताओं के लिए संख्या। 3 को 9 1955 की याचिका संख्या 243 में।

उत्तरदाताओं के लिए भवानी लाल और पी. सी. अग्रवाल नं. 3 1955 की याचिका संख्या 261 में 5 तक।

एस. एस. शुक्ला, याचिका सं. 4 में प्रतिवादी के लिए 266, 1955 से। एस. एन. आनंद, के लिए याचिका सं. 3 में प्रत्यर्थी। 362, 1955 से। के. एल. मेहता के लिए याचिका सं. 2 में प्रत्यर्थी। 205, 1956 का। 1957. 8 फरवरी। न्यायालय का निर्णय था द्वारा वितरित किया गया वेंकटरामा अय्यर जे। -- ये हैं दायर याचिकाएं कला के तहत। 32, 608 के स्वामियों द्वारा संविधान का

राजस्थान राज्य में भूमि, राजस्थान (किरायेदारों का संरक्षण) अध्यादेश के अधिकारों को चुनौती देते हुए, 1949, अध्यादेश सं। 1949 का IX, इसके बाद संदर्भित 14 जून, 1951 की अधिसूचनाओं के अध्यादेश के रूप में और 20 जून, 1953 को इसके तहत जारी किया गया और राजस्थान (किरायेदारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम नहीं। 1954 का एक्स। शुरुआत में संक्षेप में बताना उपयोगी होगा कि विधायिका के संविधान से संबंधित तथ्य प्राधिकार, जिसके प्रयोग में आक्षेपित अध्यादेश और अधिसूचनाएँ डब्ल्यूसीआरई जारी किया गया।

जब अंग्रेज इस देश के शासक थे, राजपूताना, जैसा कि राज्य को तब जाना

जाता था, में संप्रभु स्थिति का दावा करने वाली 18 रियासतें शामिल थीं। आजादी के बाद,

ए

सभी रियासतों को एक राज्य में एकीकृत करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, और यह प्रक्रिया 5 मई, 1949 को पूरी हुई थी, जब उन सभी का विलय यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजाज़ नामक संघ में हो गया था। राज्य का संविधान एक वाचा में तय किया गया था, जिस पर सभी शासक सहमत थे। कला के तहत। वाचा के दूसरे भाग में, राज्यों ने "संयुक्त राज्य राजस्थान के नाम से एक आम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ एक राज्य में अपने क्षेत्रों को एकजुट करने और एकीकृत करने" पर सहमति व्यक्त की। कला के तहत। VI (2), शासकों ने अपने सभी अधिकारों, प्राधिकारों और नए राज्य की अधिकारिता जो "उसके बाद केवल इस वाचा या उसके तहत बनाए जाने वाले संविधान द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार ही प्रयोग करने योग्य होगी"। अनुच्छेद X (3) में प्रावधान है कि,

" जब तक इस तरह से बनाया गया संविधान लागू नहीं हो जाता राजप्रमुख की सहमति प्राप्त करने के बाद, संयुक्त राज्य का विधायी प्राधिकरण राजप्रमुख में निहित होगा, जो राज्य या उसके किसी भाग की शांति और सुशासन के लिए अध्यादेश बना और जारी कर सकता है, और इस तरह बनाए गए किसी भी अध्यादेश में संयुक्त राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के समान कानून का बल होगा।

अनुच्छेद X (3) को बाद में प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया गया था। इन शब्दों के लिए "जब तक इस तरह से बनाया गया संविधान राजप्रमुख की सहमति प्राप्त करने के बाद लागू नहीं होता है," शब्द "जब तक राजस्थान की विधानसभा का विधिवत गठन नहीं हो जाता है और 609 प्रो के तहत पहले सत्र के लिए मिलने के लिए बुलाया गया संदर्भ हो सकता है भारत के संविधान के दर्शन"। कला में भी बनाया जाए। 385 भारत के संविधान के अनुसार, जो इस प्रकार चलता हैः

" विधानमंडल के सदन या सदनों तक पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट राज्य के पास है या विधिवत गठित किया गया है और बैठक के लिए बुलाया गया है संविधान के प्रावधानों के तहत पहला सत्र तत्काल कार्य करने वाला निकाय या प्राधिकरण इस संविधान के प्रारंभ से पहले संबंधित भारतीय राज्य का विधानमंडल प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करें और कर्तव्यों का पालन करें सदन पर इस संविधान के प्रावधानों द्वारा या इस प्रकार विनिर्दिष्ट राज्य के विधानमंडल के सदन।

उल्लेखनीय है कि विधान सभा राजस्थान का गठन किया गया और अस्तित्व में आया 29 मार्च, 1952 और तब तक यह राजप्रमुख था। जिसमें विधायी प्राधिकरण राज्य था निहित। राजप्रमुख ने घोषणा की कि 21 जून, 1949 को विवादित कानून, राजस्थान (का संरक्षण किरायेदार) अध्यादेश सं। 1949 का IX। प्रस्तावना में अध्यादेश इस प्रकार चलता हैः

" जबकि एक चेक लगाने की दृष्टि से भूमि मालिकों की बाहर निकालने या बेदखल करने की बढ़ती प्रवृत्त किरायेदारों को उनकी जोत से, और व्यापक राष्ट्रीय में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के हित में, यह है संरक्षण के लिए प्रावधान करना समीचीन में से निष्कासन या विस्थापन से राजस्थान में किरायेदार उनकी संपत्तियों से। अध्यादेश की धारा 4 में प्रावधान हैः

" जब तक अध्यादेश किसी भी क्षेत्र में लागू है राजस्थान का कोई भी किरायेदार बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा या उसकी पूरी या उसके हिस्से से बेदखल करना ऐसे क्षेत्र में किसी भी आधार पर। धारा 7 उन किरायेदारों की बहाली का प्रावधान करती है जो अप्रैल, 1948 के पहले दिन खराब कब्जे में था, लेकिन बाद में बेदखल कर दिया गया था और एक संशोधन अधिनियम सं। 1952 का XVII, यह अधिकार था उन किरायेदारों तक विस्तारित किया गया, जो बाद में भी कब्जे में आ गए अप्रैल का पहला दिन। 2-79 एस. सी. इंडिया/59 610

अध्यादेश की धारा 3(1)। जो बहुत भौतिक है वर्तमान याचिकाओं के लिए, इस प्रकार हैः

" यह तुरंत लागू हो जाएगा और बना रहेगा। दो वर्ष की अवधि के लिए लागू है जब तक कि यह अवधि राज प्रमुख द्वारा राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आगे बढ़ाया गया। इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज प्रमुख ने 14 जून, 1951 को एक अधिसूचना जारी की। यह प्रावधान करते हुए कि अध्यादेश सं। 1949 का IX " 21 जून, 1951 से दो साल की और अवधि के लिए लागू रहेगा"। 20 जून, 1953 को उन्होंने एक और अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि उक्त अध्यादेश" 21 जून, 1953 से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। 20 जून, 1953 की अधिसूचना की वैधता के बारे में संदेह इस आधार पर व्यक्त किया गया प्रतीत होता है कि राज्य विधानमंडल 29 मार्च, 1952 को अस्तित्व में आया था।

कला. 385

राजप्रमुख की कानून बनाने की शक्ति उस तारीख को संविधान का अंत हो गया था। संदेह को दूर करने के लिए, राजप्रमुख ने 15 फरवरी, 1954 को कला के तहत एक अध्यादेश जारी किया। 238 संविधान की सं. 1954 का III, एस के लिए प्रतिस्थापित। 3 निम्नलिखितः

" 3. यह तुरंत लागू हो जाएगा और पाँच साल की अवधि के लिए लागू रहें। इससे अध्यादेश सं. 1949 का नौवां 21 जून, 1954 तक। तब राज्य के विधानमंडल ने अध्यादेश सं. 1954 का III, और राजस्थान (किरायेदारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम सं। 1954 का X, और जो 17 अप्रैल, 1954 को लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत, एस। 3 अध्यादेश सं। 1949 का IX निम्नानुसार फिर से अधिनियमित किया गया थाः

" यह तुरंत लागू हो जाएगा और रहेगा।

सात साल की अवधि के लिए लागू।

याचिकाकर्ता अध्यादेश की वैधता पर सवाल उठाते हैं। नहीं। 1949 का IX, 14 जून की अधिसूचनाओं में से, 1951, और 20 जून, 1953 और अधिनियम सं। 1954 का एक्स। ऐसा प्रतीत होता है कि 15 अक्टूबर, 1955 को एक नया अधिनियम, राजस्थान किरायेदारी अधिनियम सं। 1955 का III लागू हुआ, और जमींदारों और किरायेदारों के बीच संबंध अब इस अधिनियम द्वारा शासित है। लेकिन एक बड़े 611 के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट एस सी आर।

ओर्डी नैन्स नं. के तहत किरायेदारों द्वारा दायर याचिकाओं की संख्या। 1919 का IX अभी भी याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त स्थगन आदेशों के कारण इन याचिकाओं पर उन्हें राहत देने के उद्देश्य से यह तय करना आवश्यक है कि क्या विवादित आदेश और अधिसूचनाएं किसी भी आधार पर खराब हैं।

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। हम तदनुसार वर्तमान याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें उनकी खूबियाँ।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने निम्नलिखित सामग्री का आग्रह किया याचिकाओं के समर्थन मेंः

(1) 14 जून, 1951 की अधिसूचनाएँ और 20 जून, 1952, एस के रूप में

खराब हैं। 3 अध्यादेश के तहत जो उन्हें जारी किया गया था, वह अधिकार से बाहर है, क्योंकि विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन।

(2) 20 जून, 1953 की अधिसूचना आगे है। बुरा, क्योंकि राजस्थान का विधानमंडल था 29 मार्च, 1952 को गठित किया गया और प्राधिकरण से राजप्रमुख को कला द्वारा प्रदत्त कानून बनाने के लिए। 385 से उस तारीख को संविधान समाप्त हो गया था।

(3) अधिनियम सं। 1954 का एक्स खराब है, क्योंकि इसका तात्पर्य है अध्यादेश सं. का जीवनकाल बढ़ाएँ। 1949 के बाद IX कहा कि अध्यादेश पहले ही मर चुका था।

(4) विवादित अध्यादेश खराब है कला के लिए अपमानजनक। 14 संविधान का; और

(5) अध्यादेश भी कला का उल्लंघन करता है। 19 (1) (जी) संविधान में कि यह अनुचित लागू करता है याचिकाकर्ताओं के अधिकार पर प्रतिबंध संपत्ति। तार्किक अनुक्रम में, यह तीसरा तर्क है कि इसे बरकरार रखा जाता है, जिसे अध्यादेश सं. का IX 1949 विवादित अधिसूचना द्वारा कवर की गई अवधि के लिए दिनांक 14 जून, 1951 और 20 जून, 1953 और उस घटना में, पहले दो विवाद नहीं बचेंगे दृढ़ संकल्प के लिए। याचिकाकर्ताओं का तर्क इस तर्क का समर्थन यह है कि भले ही दोनों में से कोई एक उपरोक्त दो अधिसूचनाएँ खराब मानी जाती हैं, तो विवादित अध्यादेश कम से कम समाप्त हो गया होगा। पर 21 जून, 1953, यदि पहले नहीं तो 21 जून, 1951 को; और वह न ही अधिनियम सं। 1954 का X जो 612 को लागू हुआ

17 अप्रैल, 1954, और न ही अध्यादेश सं। 1954 का तीसरा जिसे 15 फरवरी, 1954 को घोषित किया गया था जो पहले से ही मर चुका था उसे जीवन दें। . यह माना जाता है कि एक कानून पूर्वव्यापी हो सकता है; लेकिन यह है उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम सं। 1954 का एक्स एक स्वतंत्र नहीं था जतिन्द्र में कनिया सी. जे. की टिप्पणियों में पाया गया नाथ गुप्ता बनाम। पृष्ठ 606 पर बिहार प्रांत (1), पृष्ठ 1 पर जे. महाजन और पृष्ठ 1 पर जे. मुखर्जी पृष्ठ 643-644। हालाँकि, इस मामले पर आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं को पहले दो प्रश्नों पर अपनी दलीलों में विफल होना चाहिए।

पहला सवाल लेते हुए कि क्या एस। 3 में से अध्यादेश खराब है, जहाँ तक यह राज को अधिकृत करता है अधिनियम के जीवन को बढ़ाने के लिए प्रमुख, विवाद। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह अनिवार्य रूप से विधायी निर्धारण का विषय है कि एक क़ानून को कितने समय तक काम करना चाहिए। 3 यह प्रावधान करते हुए कि अध्यादेश दो साल की अवधि के लिए लागू होना चाहिए, उस अवधि का कोई भी विस्तार केवल विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है न कि किसी बाहरी प्राधिकरण द्वारा, और यह कि तदनुसार उस धारा द्वारा राजप्रमुख को उसमें निर्धारित अवधि को बढ़ाने के लिए प्रदत्त शक्ति विधायी शक्ति का एक असंवैधानिक प्रत्यायोजन है। जतिंद्र नाथ गुप्ता बनाम में निर्णय पर रिलायंस को इस विवाद के समर्थन में रखा गया है। बिहार प्रांत (1)। वहाँ, सवाल 7 मार्च, 1949 को बिहार सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना की वैधता के बारे में था, जिसमें 1947 के बिहार मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट V को छोटा नागपुर डिवीजन और संथाल परगना तक विस्तारित किया गया था।

16 मार्च, 1948 से पूर्वव्यापी प्रभाव से। अनुभाग (1) [1949] एफ. सी. आर. 595 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 613 एस सी आर।

1 (3) अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि यह अपने प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा, लेकिन यह एक परंतुक के अधीन था, जो निम्नानुसार थाः

" बशर्ते कि प्रांतीय सरकार, बिहार विधान सभा द्वारा पारित और बिहार विधान परिषद द्वारा सहमत एक प्रस्ताव पर अधिसूचना द्वारा निर्देश दिया जाता है कि यह अधिनियम इस तरह के संशोधन के साथ एक वर्ष की और अवधि के लिए लागू रहेगा।

अधिसूचना में निर्धारित किए गए मामले, यदि कोई हों। विचाराधीन अधिसूचना के अभ्यास में जारी किया गया था इस परंतुक के तहत प्रदत्त शक्ति, और यह न्यायालय के बहुमत द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि परंतुक असंवैधानिक था क्योंकि यह विधायी प्राधिकरण के प्रत्यायोजन के बराबर था, और इसलिए, इसके अनुसार जारी की गई अधिसूचना खराब थी। तीन विद्वान न्यायाधीशों ने यह विचार व्यक्त किया कि किसी अधिनियम के संचालन को बढ़ाने की शक्ति विशुद्ध रूप से एक विधायी कार्य था, और इसे किसी बाहरी प्राधिकरण को नहीं सौंपा जा सकता था। इस प्रकार, कनिया सी. जे. ने पृष्ठों पर अवलोकन किया 604-605 :

" अधिनियम के संचालन का विस्तार करने की शक्ति अधिनियम में उल्लिखित अवधि से परे प्रथम दृष्टया एक विधायी शक्ति है। यह विधानमंडल को बताना है

कि कोई विशेष कानून कितने समय तक लागू रहेगा। इसे किसी अन्य निकाय के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। यहां तक कि अधिनियम को संशोधित करने की शक्ति को अलग रखते हुए, मैं प्रांतीय द्वारा सशर्त कानून के रूप में शब्दबद्ध परंतुक का अर्थ लगाने में असमर्थ हूं। सरकार। धारा 1 (3) और गेदर को पढ़े गए परंतुक की ठीक से व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि बिहार सरकार ने अपने विधायी कार्यों के निष्पादन में अधिनियम के जीवन को इससे आगे निर्धारित किया था।

अवधि के बाद भी इसके निरंतर अस्तित्व के लिए एक वर्ष। एक वर्ष के लिए इसने अपनी इच्छा या निर्णय का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इसे दूसरे प्राधिकरण पर छोड़ दिया था। नहीं था प्रांत का विधायी प्राधिकरण"। महाजन जे. ने इस प्रश्न पर टिप्पणी की पृष्ठ 623: " मैं राय से आगे हूँ कि शक्ति दी गई है अधिनियम के जीवन का विस्तार करने के लिए एक और वर्ष में एस की भाषा का संदर्भ। 1 (3) यह भी कानून के एक अधिनियम के बराबर है और निर्धारित नियम [1957] के तहत नहीं आता है। 614 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट द क्वीन वी में नीचे। बुराह (1)। एक अनिवार्य रूप में अधिनियम में कहा गया है कि यह केवल एक वर्ष के लिए लागू होगा। ऐसा होने पर, परंतुक में दी गई शक्ति पुनः इसे एक और वर्ष के लिए लागू करना विधायी शक्ति है और यह सशर्त कानून के बराबर नहीं है। जे. मुखर्जी की राय थी कि यदि विधान यह किसी बाहरी प्राधिकारी द्वारा किसी तथ्य या शर्त के निर्धारण पर प्रभावी होना था, यह सशर्त विधान होगा, और यह इस पर मान्य होगा "किसी भावी तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अधिनियम को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए" संशोधनों के साथ या बिना"। जे. फजल अली ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने पृष्ठ 646 पर कहाः

" जहाँ तक अधिनियम के विस्तार का संबंध है, । मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह कानून बनाने या विधायी शक्ति के प्रयोग के बराबर है। अधिनियम से, यह स्पष्ट है कि, हालांकि यह पहली बार में एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहा, विधायिका ने किया ए के लिए बढ़ाया गया विचार करें कि यह एक वर्ष की और अवधि हो सकती है। निर्णय लेने के बाद कि वह विस्तार करना पड़ सकता है, उसने मामला छोड़ दिया में से प्रांतीय के विवेक के लिए विस्तार शासन करें। मन में। मुझे ऐसा लगता है कि विधानमंडल ने उस अवधि के बारे में अपने निर्णय का प्रयोग किया है जिसके लिए अधिनियम लागू था या रहना पड़ सकता है, इसके सशर्त विधान में कुछ भी गलत नहीं था और इसे कार्यकारी प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया था।

क्या अधिनियम को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। यह बुरा के मामले (1) में निर्णय के बारे में कुछ संकीर्ण दृष्टिकोण लेना होगा कि यह अभिनिर्धारित करना कि विधायिका सशर्त रूप से कानून बनाते समय केवल समय और समय छोड़ सकती है। अपने विधान को कार्यकारी प्राधिकारी के गठन तक प्रभावी बनाने का तरीका और यह कि वह नहीं कर सकता है किसी भी अन्य मामले को उसके विवेक पर छोड़ दें। एक वर्ष की और अवधि के लिए अधिनियम का विस्तार इसके पुनः अधिनियमन के बराबर नहीं है। यह केवल विधानमंडल द्वारा इसे अधिनियमित करते समय निर्धारित अधिकतम अवधि के लिए अधिनियम को जारी रखने के बराबर है। (1) [1878] एल. आर. 5 आई. ए. 178. एस सी आर।

यह ध्यान दिया जाएगा कि प्रदत्त अधिकार एस के परंतुक द्वारा बिहार सरकार। 3 यह न केवल वर्तमान मामले की तरह अधिनियम के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए था, बल्कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए ऐसे संशोधनों के साथ इसे बढ़ाने के लिए भी था। यह बाद वाला खंड है जो मुख्य रूप से बहुमत के निर्णयों में हमले के लिए आया था, और यह निर्णय कि समग्र रूप से परंतुक खराब था, मुख्य रूप से इस दृष्टिकोण पर आधारित था कि वह खंड अधिकार से बाहर था। कनिया सी. जे. ने निस्संदेह कहा कि अधिनियम के संचालन को बढ़ाने की शक्ति, इसे संशोधित करने की शक्ति के अलावा, एक विधायी कार्य था। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति एकल थी और अधिनियम के जीवन को बढ़ाने की शक्ति को इसे संशोधित करने की शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। जे. मुखर्जी ने बॉम्बे राज्य बनाम में अपने फैसले में इस मामले को और भी स्पष्ट कर दिया था। नरोत्तमदास जेठाबाई (1)। वहाँ, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा था

जतिंद्र नाथ गुप्ता बनाम। . बिहार प्रांत (2), अर्थात। 4 बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट एक्ट, 1948, जिसने राज्य को निवेश करने का अधिकार प्रदान किया सिविल न्यायालयों को अधिसूचना द्वारा अधिकार क्षेत्र के साथ रुपये से अधिक के मुकदमों की सुनवाई करने के लिए। 25,000 खराब था। इस निष्कर्ष से असहमत होते हुए, जे. मुखर्जी ने कहाः

" बम्बई उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश इस मुद्दे पर अपने निर्णय पर आने में ऐसा लगता है कि जतिंद्रनाथ गुप्ता बनाम में संघीय न्यायालय की घोषणा से कुछ हद तक प्रभावित हुआ है।

बिहार प्रांत (2), और विद्वान। के लिए वकील उत्तरदाताओं ने स्वाभाविक रूप से निर्भरता रखी उस पर। श्री सीरवई ने उस मामले में अपने पक्ष में एक प्राधिकरण के रूप में निर्णय का आह्वान करना शायद सही होता यदि परंतुक केवल शर्तों के अनुपालन पर प्रांतीय सरकार को सशक्त बनाता। अधिनियम की अवधि को एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाने के लिए, अधिकतम अवधि विधानमंडल द्वारा ही निर्धारित की जा रही है।

द.
प्रावधान, हालाँकि, आगे बढ़े और अधिकृत किया प्रांतीय सरकार वर्ष के अंत में न केवल यह तय करेगी कि क्या अधिनियम को एक और वर्ष के लिए जारी रखा जाना चाहिए, बल्कि यह भी तय करेगी कि क्या अधिनियम को ही किसी अन्य वर्ष में संशोधित किया जाना है। (1) [1951] एस. सी. आर. 51 (2) [1949] एफ. सी. आर. 595.

रास्ता या नहीं। यह विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया गया था कानून में संशोधन करने के लिए एक अन्य निकाय निवेश के बराबर है। विधायी शक्तियों वाला वह निकाय। क्या सीखा है वकील ने तर्क दिया कि संशोधन की शक्ति प्रावधान संविधि की अवधि बढ़ाने की शक्ति से अलग किया जा सकता था और परंतुक के एक भाग की अयोग्यता से इसका दूसरा भाग प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस तर्क के लिए मेरा जवाब था कि दो प्रावधान थे कानून में इस तरह से अंतर-संबंधित है कि एक अन्य"। से अलग नहीं किया जा सकता जतिंद्र नाथ में निर्णय गुप्ता गुप्ता बनाम। प्रांत इसलिए बिहार का (1) नहीं हो सकता है स्पष्ट माना जाता है और कि एक वैधानिक प्रावधान प्रत्यक्ष घोषणा एक बाहरी को अधिकृत करना जीवन का विस्तार करने का अधिकार एक क़ानून अपने आप में बुरा है। अब हमें इन द में निर्णय का उल्लेख करना चाहिए दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 (2 ए) जिसमें प्रत्यायोजित विधान से संबंधित कानून की व्यापक समीक्षा की गई थी यह न्यायालय। वह कला के तहत एक संदर्भ था। 143 इस न्यायालय की राय के लिए कई प्रश्न बताते हुए संविधान। अनुमेय प्रत्यायोजन की सीमाओं के बारे में कई निर्णयों में व्यक्त किए गए विचारों में काफी भिन्नता के कारण, निर्दिष्ट प्रश्नों के उत्तरों में कोई सर्वसम्मति नहीं हो सकी। लेकिन कानून के कुछ प्रस्तावों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्हें अधिकांश विद्वानों का समर्थन प्राप्त था।

जब एक न्यायाधीश, और ऐसा ही एक प्रस्ताव है कि अधिकृत करता है उपयुक्त विधानमंडल एक कानून बनाता है और ऐसे में बल एक बाहरी प्राधिकरण जिसे इसे क्षेत्र में लाने के लिए या ऐसे समय पर जो वह तय करे, वह सशर्त है और प्रत्यायोजित विधान

नहीं है, और यह कि कानून वैध है। हमारी राय में, एस। 3 में से द क्वीन बनाम में प्रिवी काउंसिल का निर्णय। बुराह (3)। वहाँ, एक अधिसूचना की वैधता के बारे में सवाल था बंगाल के उपराज्यपाल द्वारा जारी किया गया प्रशस्ति पत्र (1) [1949] एफ. सी. आर. 595. (2) [1951] एससीआर 747। (3) [1878] 5 आई. ए., 178. 617 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट एस सी आर। 14 अक्टूबर, 1871 को अधिनियम सं। एस द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में 1869 का XXII, जयंतिया और खासी पहाड़ियों के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र को दिया गया। 9 उस अधिनियम का, जो इस प्रकार थाः

"उक्त उपराज्यपाल समय-समय पर समय-समय पर, कलकत्ता राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की अन्य धाराओं में निहित सभी या किसी भी प्रावधान का विस्तार जयंतिया पहाड़ियों, नागा पहाड़ियों और खासी पहाड़ियों के ऐसे हिस्से तक किया जाता है जो कुछ समय के लिए ब्रिटिश भारत का हिस्सा हैं।

उच्च न्यायालय ने बहुमत से कहा था कि विधायी प्राधिकरण के प्रत्यायोजन के रूप में यह धारा अधिकार से बाहर थी। लेकिन उस निर्णय को प्रिवी काउंसिल में अपील करने पर उलट दिया गया, जिसने माना कि यह सशर्त कानून था, और वैध था। लॉर्ड सेलबोर्न ने कानून को इस प्रकार कहाः

" उनके अधिपति इस बात से सहमत हैं कि राज्यपाल-जीन परिषद किसी भी प्रकार के अधिनियम द्वारा ऐसा नहीं कर सकी। में भारत, और सामान्य विधायी के साथ हाथ बनाएँ प्राधिकरण, एक नया विधान नहीं बनाया गया शक्ति, या परिषद अधिनियम द्वारा प्राधिकृत। उनके स्वामी की राय में, वर्तमान मामले में इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया है या प्रयास नहीं किया गया है। क्या किया गया है। यह है। गवर्नर-जनरल इन काउंसिल ने किसी विशेष जिले को सामान्य न्यायालयों और कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र से हटाने और इसे नए न्यायालयों और कार्यालयों के तहत रखने के लिए खनन किया है, जिसे बंगाल के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाना है और यह उपराज्यपाल पर छोड़ दिया है कि वह यह बताए कि वह किस समय बदलता है। होगा.. द लेजिस प्रकृति निर्धारित की गई कि, अब तक, एक निश्चित परिवर्तन होना चाहिए लेकिन यह कि इसे लागू करने का समय और तरीका उपराज्यपाल के विवेक पर छोड़ना समीचीन था। उचित विधानमंडल ने अपने निर्णय का प्रयोग किया कि जगह, व्यक्ति, कानून, शक्तियाँ और उस निर्णय का परिणाम इन सब के बारे में सशर्त कानून बनाना हो चुका है चीज़ें। शर्तें पूरा होने के बाद, जहाँ की पूर्ण शक्तियाँ कानून अब निरपेक्ष है। विशेष विषयों के बारे में कानून मौजूद हैं, चाहे वे किसी शाही या प्रांतीय विधानमंडल में हों, वे (618 में)

उनके प्रभुता के निर्णय) का अच्छी तरह से प्रयोग किया जाए, या तो बिल्कुल या सशर्त। कानून, सशर्त विशेष शक्तियों के उपयोग पर या एक के प्रयोग पर विधानमंडल द्वारा सौंपे गए सीमित विवेकाधिकार जिन व्यक्तियों में यह विश्वास रखता है, वे असामान्य नहीं हैं। बात; और, कई परिस्थितियों में, यह अत्यधिक हो सकता है सुविधाजनक। ब्रिटिश क़ानून पुस्तक प्रचुर मात्रा में है। के साथ इसके उदाहरण; और यह नहीं माना जा सकता है कि शाही संसद ने गठन करते समय नहीं किया था भारतीय विधानमंडल, के दायरे में इस तरह के सशर्त विधान पर विचार करें विधायी शक्तियाँ जो उसने समय-समय पर प्रदान की हैं।

यह स्पष्ट अधिकार है कि एक क़ानून में एक प्रावधान किसी बाहरी प्राधिकारी को ऐसे समय में इसे लागू करने की शक्ति प्रदान करना, जो वह अपने स्वयं के विवेक में निर्धारित कर सके, सशर्त है और प्रत्यायोजित कानून नहीं है, और यह वैध होगा, जब तक कि संविधान अधिनियम में इसकी शक्ति पर कोई सीमा न हो। इस तरह का कानून बनाएँ।

याचिकाकर्ता इस पर विवाद नहीं करते हैं। वे क्या हैं? तर्क यह है कि जबकि यह सक्षम हो सकता है विधानमंडल यह तय करने के लिए किसी बाहरी प्राधिकरण पर छोड़ दे कि कोई अधिनियम कब लागू किया जा सकता है, यह उसके लिए यह अधिकृत करने के लिए सक्षम नहीं है कि वह प्राधिकरण अधिनियम के जीवन को निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। उसमें। सिद्धांत रूप में, यह देखना मुश्किल है कि अगर एक सक्षम है, तो दूसरा क्यों नहीं है। किसी अधिनियम को उस समय लागू करने के लिए एक बाहरी प्राधिकरण को अधिकृत करने वाले विधायी प्रावधान को बनाए रखने का कारण यह है कि इसे तथ्यों पर निर्भर करना चाहिए क्योंकि वे एक निश्चित समय पर मौजूद हो सकते हैं, जहां कानून को तब लागू किया जाना चाहिए, और यह कि इस तरह के मुद्दे का निर्णय एक कार्यकारी प्राधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस तरह के विधान को सशर्त कहा जाता है, क्योंकि विधानमंडल ने स्वयं "स्थान, व्यक्ति, कानून, शक्तियों" के संबंध में कानून को अपनी पूरी पूर्णता में बनाया है, कानून बनाने के लिए बाहरी प्राधिकरण के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। पर, इसे सौंपा गया एकमात्र कार्य कानून को ऐसे समय पर लागू करना है जब वह तय कर सके। और यह एक सशर्त विधान के रूप में एक विधान के चरित्र में कोई अंतर नहीं ला सकता है कि विधायिका, कानून को लागू करने और तय करने के बाद, एक विचार पर। 619 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट एस. सी. आर।

उन तथ्यों में से जो उस समय मौजूद हो सकते थे, इसकी अवधि, एक बाहरी प्राधिकरण को एक और अवधि के लिए अपने संचालन को बढ़ाने की शक्ति प्रदान करती है यदि यह संतुष्ट है कि तथ्यों की स्थिति जो कानून को आगे बढ़ाती है, बनी हुई है।

वर्तमान मामले में, अध्यादेश की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से उन तथ्यों की स्थिति का पाठ करता है जिनके कारण विचाराधीन कानून के अधिनियमन की आवश्यकता थी, और एस। 3 उस समय की स्थिति को समझने के लिए अधिनियम की अवधि दो वर्ष निर्धारित की गई। साथ ही, इसने राजप्रमुख को अध्यादेश अध्यादेश के जीवन को उस अवधि से आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान की, यदि स्थिति की आवश्यकता होती है।

जब ऐसा होता है विस्तार राजप्रमुख द्वारा तय किया जाता है और अधिसूचित किया जाता है, जो कानून काम करेगा वह कानून है जिसे "स्थान, व्यक्ति, कानून, शक्तियों" के संबंध में विधायी प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित किया गया था, और यह स्पष्ट रूप से सशर्त है और प्रत्यायोजित कानून नहीं है जैसा कि राजप्रमुख में निर्धारित किया गया है।

रानी वी. बुराह (1), और परिणामस्वरूप, वैध माना जाना चाहिए। इस प्रकार हम सहमत होने में असमर्थ हैं।

जतिंद्र नाथ गुप्ता बनाम में कानून के कथन के साथ। बिहार राज्य (2) कि किसी अधिनियम के जीवनकाल को बढ़ाने की शक्ति वैध रूप से प्रदान नहीं की जा सकती है एक बाहरी प्राधिकरण। इस दृष्टिकोण से, विधायी प्रत्यायोजन की अनुमेय सीमाओं के बारे में प्रश्न जिस प्राधिकारी पर दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 (3) में दिए गए निर्णय विचारों के तीव्र टकराव को प्रकट करते हैं, वह विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता है और हम उस पर अपनी राय सुरक्षित रखते हैं।

(2) इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि अधिसूचना 20 जून, 1953 की तारीख खराब है, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद, राजप्रमुख ने अनुच्छेद से कानून बनाने का अपना अधिकार प्राप्त किया। 385, और यह कि उस अनुच्छेद के तहत उनका अधिकार तब समाप्त हो गया जब राज्य के विधानमंडल का गठन किया गया, जो वर्तमान मामले में 29 मार्च, 1952 को था। यह तर्क एस के तहत जारी अधिसूचना के सही चरित्र के बारे में एक गलत धारणा पर आगे बढ़ता है। 3 अध्यादेश का। ऐसा नहीं था।

जितना हो सकता है एक स्वतंत्र टुकड़ा इस तरह का कानून केवल द्वारा अधिनियमित किया जाए तब सक्षम विधायी (2) [1949] एफ. सी. आर. 595. (1) [1878] 5

आई. ए. 178. (3) [1951] एससीआर 747। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1957] 620 अध्यादेश। यदि अध्यादेश इस तथ्य के कारण समाप्त नहीं हुआ कि राज प्रमुख का कानून बनाने का अधिकार समाप्त हो गया था-और यह विवादित नहीं है और न ही किया जा सकता है - न ही अधिसूचना जारी करने की शक्ति जो उसमें प्रदान की गई है। सच है। स्थिति यह है कि यह अधिकार के रूप में उसके चरित्र में है जिसे एस के तहत शक्ति प्रदान की गई थी। 3 में से अध्यादेश पर कि राजप्रमुख ने विवादित अधिसूचना जारी की, न कि राज्य के विधायी प्राधिकरण के रूप में। तदनुसार इस आपत्ति को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(4) हम आगे इस तर्क पर विचार करेंगे कि अध्यादेश के प्रावधान कला के प्रतिकूल हैं। 14 संविधान का, और इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि यह शून्य हो गया है। हमारे सामने तर्क में, हमला मुख्य रूप से एसएस के खिलाफ किया गया था। 7 (1) और अध्यादेश का 15. एस के संदर्भ में विवाद। 7 (1) यह है कि उस धारा के तहत मकान मालिक जिनके पास किरायेदार थे 1 अप्रैल, 1948 को उनकी भूमि पर, उनके अधिकारों के आनंद में विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन थे मालिक, जबकि अन्य मकान मालिक इसी तरह के प्रतिबंधों से मुक्त थे। इस तर्क में कोई सार नहीं है। अध्यादेश की प्रस्तावना में कहा गया है कि भूस्वामियों की ओर से किरायेदारों को बाहर निकालने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और इसलिए उन्हें सुरक्षा देने के लिए एक कानून बनाना समीचीन था और उन्हें राहत देने के लिए, विधानमंडल को अनिवार्य रूप से - यह तय करें कि कानून को किस तारीख से लागू किया जाना चाहिए, और यह तय किया कि यह 1 अप्रैल, 1948 से होना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जिसे विशेष रूप से विधानमंडल को निर्धारित करना है, और उस निर्धारण का औचित्य है -

अदालतों में सवाल करने के लिए खुला नहीं है। हमें यह जोड़ना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावना में पाठ की शुद्धता पर विवाद करने की मांग की थी। वे स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कर सकते। ब्लॉक वी. में जे. होम्स की टिप्पणियों को देखें। हिर्श (1)।

(1) [1920] 256 अमेरिका 135: 65 एल. एड. 865 . सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 621 एस सी आर।

एक अधिक महत्वपूर्ण विवाद इस पर आधारित है कि एस. 15, जो सरकार को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अधिनियम के संचालन से छूट देने के लिए अधिकृत करता है। यह तर्क दिया जाता है कि यह धारा उन सिद्धांतों को निर्धारित नहीं करती है जिन पर छूट दी जा सकती है, और यह कि मामले का निर्णय सरकार के

निरंकुश और अप्रमाणित विवेक पर छोड़ दिया जाता है, और इसलिए यह अनुचित है -कला. 14. यह सच है कि धारा स्वयं उन आधारों को इंगित नहीं करती है जिन पर छूट दी जा सकती है, लेकिन अध्यादेश की प्रस्तावना में विधानमंडल की नीति को पर्याप्त स्पष्टता के साथ निर्धारित किया गया है; और जैसा कि एस। 15 अध्यादेश का निर्णय इसके तहत सरकार इसे दिशाहीन नहीं कहा जा सकता। वीडियो हरिशंकर बागला बनाम. मध्य प्रदेश राज्य (1) लेकिन फिर भी एस. 15 बुरा माना जाना था, जो प्रभावित नहीं करता है बाकी कानून, जैसा कि उस मामले में निपटाया गया था खंड स्पष्ट रूप से अलग करने योग्य है। वास्तव में, एस। 15 में नहीं था अध्यादेश जैसा कि यह मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, और केवल बाद में अध्यादेश सं। 1949 का बारहवाँ। हमें तदनुसार यह मानना चाहिए कि विवादित अध्यादेश को अनुच्छेद के तहत गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

14. अंत में यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम के प्रावधान वे कला के प्रतिकूल हैं। 19 (1) (च) कि वे बाध्य करते हैं भूमि-मालिकों को किरायेदारों को रखने के लिए। अपनी भूमि पर, जिससे उन्हें उसी की खेती करने से रोका जा सके।

अध्यादेश का उद्देश्य, जैसा कि प्रस्तावना में निर्धारित किया गया है, स्पष्ट रूप से इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना है - एक का अधिकार मालिक स्वयं भूमि पर खेती करता है, लेकिन रोकने के लिए भूमि से जब उन्होंने पर्याप्त कारण के बिना उससे छुटकारा पाने के लिए एक किरायेदार को शामिल किया था। एक कानून जिसके लिए आवश्यक है कि एक मालिक जो खुद मिट्टी का जुताई करने वाला नहीं है, उसे वास्तविक जुताई करने वाले को कार्यकाल की कुछ निश्चितता का आश्वासन देना चाहिए, अकेले उस आधार पर अनुचित नहीं कहा जा सकता है। अमेरिका में इस चरित्र के कानून को किसी भी संवैधानिक उल्लंघन के रूप में बरकरार रखा गया है। गारंटी। इस प्रकार, खंड v में। हिर्श (2), एक कानून जिसने किरायेदारों को अधिकार में बने रहने का अधिकार दिया लीज की समाप्ति के बाद, वैध माना गया था, जे. होम्स ने कहा, (1) [1955] 1 एस. सी. आर 380 388. (2) [1920] 256 यू. एस. 135; 65 एल एड। 865 . [1957] सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 622

" कानून के खिलाफ मुख्य बात यह है कि किरायेदार हैं उसी किराए पर कब्जे में रहने की अनुमति दी गई है जो वे भुगतान कर रहे हैं, जब तक कि अधिनियम द्वारा स्थापित आयोग द्वारा संशोधित नहीं किया जाता है, और इस प्रकार भूमि और मालिक का अधिकार कि वह अपने साथ जो चाहे करे और जो अनुबंध वह चाहे करे काट

दिए जाते हैं। लेकिन यदि लोक हित स्थापित किया जाता है, तो दरों का विनियमन उन पहले रूपों में से एक है जिसमें इसका दावा किया जाता है, और इस तरह के विनियमन की वैधता मुन्न बनाम के बाद से बसाया गया। इलिनोइस के लोग (1)। कब्जे में किरायेदार को दी जाने वाली वरीयता पॉलिसी का एक लगभग आवश्यक घटक है, और अंग्रेजी कानून में पारंपरिक है। यदि किरायेदार बेदखल करने की मकान मालिक की शक्ति के अधीन रहता है, तो मकान मालिक की मांगों को सीमित करने का प्रयास विफल हो जाएगा।

इस संबंध में यह भी याद रखना चाहिए कि विवादित अध्यादेश एक अस्थायी चरित्र का एक आपातकालीन कानून है, और जैसा कि डॉ. एन. बी. में देखा गया है। खरे वी. दिल्ली राज्य (*), यह एक ऐसा कारक है जिसे इसकी तर्कसंगतता का आकलन करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अध्यादेश तब से समाप्त हो गया है और एक व्यापक व्यापक किरायेदारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इन परिस्थितियों में, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि विवादित अध्यादेश अमान्य है क्योंकि यह इसके विपरीत है कला की कला। 19 (1) (च)।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई सभी दलीलें विफल रहा, और याचिकाओं को तदनुसार खारिज कर दिया जाना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों में, बिना किसी लागत के। याचिकाएं खारिज कर दी गईं। (8 1) (2) [1877] 94 अमेरिका 113: 24 एल. एड. 77 . [1950] एस. सी. आर. 519,526

अखिलेश कुमार